भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Ref. No.: LIC/SE/2026-27/81 Date: August 07, 2026

To
The Manager
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai–400001

Scrip Code: 543526

The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051

Scrip Code: NSE - LICI

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2026.

The Board of Directors in its Meeting held on August 06, 2026 inter-alia, has approved the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results ("Financial Results") of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation") for the quarter ended June 30, 2026.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are published in the Business Standard (Hindi and English), Navshakti (Marathi) and Free Press Journal (English) in the prescribed format on August 07, 2026. A copy of the Financial Results published in the above-mentioned newspapers are enclosed herewith.

Please take the above information on record and arrange for its dissemination. A copy of this intimation is also being made available on website of the Corporation at www.licindia.in .

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

ANSHUL KUMAR SINGH
Digitally signed by ANSHUL KUMAR SINGH
Date: 2026.08.07 12:52:34 +05'30'

(Anshul Kumar Singh)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

चौथे दिन भी सेंसेक्स-निफ्टी में अंतर

बाजार में उतार-चढ़ाव का पैमाना इंडिया विक्स गुरुवार को 0.8 फीसदी बढ़कर 12.15 पर बंद हुआ

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 6 अगस्त

अजय मोहंती

भारत के बेंचमार्क शेयर सूचकांकों में लगातार चौथे दिन भी अंतर बरकरार रहा। इस दौरान निवेशक वायदा एवं विकल्प अनुबंध वाले शेयरों के लिए प्राइस-डिस्कवरी मैकेनिज्म में हुए बदलावों से जूझते रहे। सेंसेक्स और निफ्टी के बीच यह अंतर 0.43 फीसदी रहा।

दोपहर 3:15 बजे निफ्टी 24,628 पर था। लेकिन गुरुवार का सत्र 24,636 पर खत्म हुआ, जो प्री-क्लोजिंग ऑक्शन के स्तर से 0.03 फीसदी ज्यादा था। दोपहर 3:15 बजे सेंसेक्स 78,785.6 पर था, लेकिन सत्र के आखिर में 78,954.8 पर बंद हुआ, यानी आखिरी 20 मिनट में इसमें 0.21 फीसदी की बढ़त हुई। सेंसेक्स में यह तेज हलचल इंडेक्स से जुड़े साप्ताहिक डेरिवेटिव अनुबंधों की एक्सपायरी की वजह से हुई। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज में डेरिवेटिव और टेक्निकल शोध के प्रमुख चंदन तापड़िया ने कहा, क्लोजिंग ऑक्शन में भागीदारी कम रहती है, जिससे ऑर्डरों की थोड़ी सी संख्या का भी इंडेक्स के आखिरी स्तर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। गुरुवार को साप्ताहिक सेंसेक्स एक्सपायरी की वजह से बीएसई में सूचीबद्ध शेयरों में ऑक्शन की ज्यादा गतिविधियां हुई, जिससे सेंसेक्स में तेजी से उतार-चढ़ाव आया। लेकिन निफ्टी में ऐसी गतिविधि न होने के कारण वह काफी हद तक स्थिर रहा।

क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम के तहत जिन शेयरों में वायदा एवं विकल्प अनुबंध होते हैं, उनके बंद भाव दोपहर 3:15 बजे से 3:35 बजे के बीच होने वाली खरीद-फरोख्त (ऑक्शन) के ऑर्डरों के मिलान से तय किए जाते हैं। पहले आखिरी 30 मिनट में हुए सौदों की 'वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस' का इस्तेमाल करके भाव निकाले जाते थे। उसकी जगह यह तरीका लाया गया है। जिन शेयरों में डेरिवेटिव अनुबंध नहीं होते, उनमें पुराना तरीका ही इस्तेमाल हो रहा है।

बाजार में उतार-चढ़ाव का पैमाना इंडिया विक्स गुरुवार को 0.8 फीसदी बढ़कर 12.15 पर बंद हुआ। उतार-चढ़ाव वाला यह संकेतक इस हफ्ते अब तक 3.4 फीसदी बढ़ा है। ब्रोकरों के फोरम एएनएमआई के अध्यक्ष कमलेश श्रॉफ ने कहा कि यह अंतर मुख्य रूप से नए सिस्टम से जुड़े लर्निंग कर्व के कारण था।

श्रॉफ ने कहा, सीमित भागीदारी और ज्यादा जागरूकता की जरूरत, ये दो मुख्य कारण हैं। जैसे-जैसे बाजार के ज्यादा प्रतिभागी इस प्रक्रिया से परिचित होंगे और सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे, प्राइस डिस्कवरी ज्यादा कुशल होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगस्त के आखिर तक बाजार सीएएस के तहत पूरा साप्ताहिक और मासिक सेटलमेंट चक्र पूरा कर लेगा। तब तक भागीदारी बढ़नी चाहिए और अंतर काफी कम हो जाना चाहिए।

बरकरार है अंतर

क्लोजिंग ऑक्शन में भागीदारी कम रहती है, जिससे ऑर्डरों की थोड़ी सी संख्या का भी इंडेक्स के आखिरी स्तर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है

गुरुवार को साप्ताहिक सेंसेक्स एक्सपायरी की वजह से बीएसई में सूचीबद्ध शेयरों में ऑक्शन की ज्यादा गतिविधियां हुई, जिससे सेंसेक्स में तेजी से उतार-चढ़ाव आया

थोड़ी बढ़त के साथ सात हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा सोना

रॉयटर्स

सोने की कीमतें गुरुवार को सात हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और लगातार चौथे दिन इनमें इजाफा हुआ। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलने की उम्मीदों ने महंगाई और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों को लेकर बढ़ रही चिंताओं को कम कर दिया। इस कारण सोने के भावों में इजाफा हुआ।

हाजिर सोना 0.4 फीसदी बढ़कर 4,261.86 डॉलर प्रति औंस पर जा पहुंचा। इससे पहले यह 18 जून के बाद के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। बुधवार को सोने में फरवरी के बाद की सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त दर्ज की गई थी और इसकी कीमत 4,267.24 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.4 फीसदी की बढ़त के साथ 4,321.40 डॉलर पर पहुंच गया।

जेफ़रीज की कंपनी ट्रेडू डॉट कॉम के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक निकोस जाबोरस ने कहा, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ती उम्मीदों के बीच सोना आज अपनी हाल की बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक समाधान से तेल की आपूर्ति फिर से शुरू होने की उम्मीदों के कारण महंगाई का डर घट रहा है और फेड के सख्त रुख की संभावनाओं पर भी लगाम लग रही है।

ईरान और ओमान के बीच प्रस्तावित डील से ईरान और अमेरिका के बीच पांच महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिल सकती है। रॉयटर्स को ईरान के एक वरिष्ठ सूत्र और इलाके के दो अधिकारियों ने बताया कि इस डील से तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट से खाड़ी में आने वाले जहाजों पर नियंत्रण मिल जाएगा। सितंबर में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की बाजार की उम्मीदें दो दिन पहले की 67 फीसदी से घटकर 55 फीसदी रह गई हैं।

आमतौर पर सोने को महंगाई से बचाव का ज़रिया माना जाता है, लेकिन ऊंची ब्याज दरों वाले माहौल में इससे कोई कमाई नहीं होती। इसलिए इसका आकर्षण कम हो जाता है। सैन फ्रांसिस्को के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रेसिडेंट मैरी डेली ने कहा कि वह पिछले हफ्ते ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले का पूरी तरह समर्थन करती हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक और आंकड़े इकट्ठा कर रहा है कि महंगाई, जो उसके 2 फीसदी के लक्ष्य से काफी ज्यादा है, को लेकर वह क्या कदम उठाए।

निवेशक शुक्रवार को आने वाली जुलाई की अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एडीपी की नैशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से पता चला है कि जुलाई में अमेरिका में प्राइवेट पेरोल की वृद्धि धीमी हो गई। जाबोरस ने कहा, सोने पर फिर से दबाव पड़ने और 2026 के नए निचले स्तर पर जाने का खतरा बना हुआ है। कीमतों का दबाव बना हुआ है, जिससे ब्याज दरें बढ़ाने का विरोध करने वाले सक्रिय हैं और भूराजनीतिक जोखिम भी बने हुए हैं।

रक्षा शेयरों ने मार्केट कैप में जोड़े 2.5 लाख करोड़ रु.

अभिनव रंजन
नई दिल्ली, 6 अगस्त

इस साल जून तिमाही में रक्षा से जुड़ी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 2.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इससे उनका कुल मार्केट कैप 12.47 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऐस इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान जहां निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में करीब 31 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं पारस डिफेंस, एमटीएआर टेक्नॉलजीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स जैसे शेयरों में 100 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई।

इसकी तुलना में इस अवधि में निफ्टी 50 इंडेक्स में करीब 7 फीसदी की बढ़त हुई। जुलाई में 3.4 फीसदी की मामूली गिरावट के बाद, जिससे उसकी लगातार तीन महीने की बढ़त का सिलसिला टूट गया था, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने अगस्त में अब तक करीब 4 फीसदी की बढ़त दर्ज की है।

विश्लेषकों का कहना है कि जून तिमाही में हुई बढ़त को मजबूत ऑर्डर बुक और पॉलिसी समर्थन से मदद मिली। इसके अलावा, भूराजनीतिक हालात ने भी एक तरह से मदद की क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई की वजह से खाड़ी देशों में रक्षा बजट को लेकर तेजी से कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई।

विश्लेषकों का कहना है कि जुलाई में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में आई गिरावट मुख्य रूप से शानदार तेजी के बाद मुनाफावसूली का नतीजा थी। उन्होंने यह भी बताया कि इंडेक्स लगभग 56 गुना के पीई मल्टीपल पर कारोबार कर रहा था, जो उसके पांच साल के औसत 44.9 गुना से काफी ज्यादा है। लिहाजा, निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

लंबी अवधि का सकारात्मक परिदृश्य

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सेक्टर का लंबी अवधि का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, जिसकी वजह मजबूत ऑर्डर बुक है, जिससे कई सालों तक राजस्व मिलने का भरोसा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकारी पहल, रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी और स्वदेशीकरण पर लगातार फोकस से इस सेक्टर की ढांचागत वृद्धि की कहानी और मजबूत हो रही है।

निवेश के नजरिये से रेलिगेयर ब्रोकिंग में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्र ने कहा कि एकमुश्त निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा लगता है। उन्होंने कहा, लंबे समय के लिए निवेश करने वाले लोग बाजार में गिरावट के समय का फायदा उठाकर ऐसी मजबूत कंपनियों में धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं, जिनका काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके पास अच्छे ऑर्डर हैं और जिनके लिए निर्यात के मौके बढ़ रहे हैं।

आईसीआईसीआई सिक्यो. के विश्लेषकों ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को लेकर उनका रुख सकारात्मक है। सरकार की नीतियां लगातार सहायक बनी हुई हैं, जिसका सबूत रक्षा मंत्रालय का कैलेंडर वर्ष 29 तक 3 लाख करोड़ रुपये का सालाना पूंजीगत व्यय का लक्ष्य है।

ईरान-ओमान वार्ता पर निवेशक सतर्क, कच्चा तेल चढ़ा

रॉयटर्स

कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार को बढ़ोतरी हुई क्योंकि निवेशक ईरान-ओमान बातचीत के नतीजों और इस बात को लेकर सतर्क थे कि होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आपूर्ति फिर से शुरू होगी या नहीं। वहीं, लाल सागर और अदन की खाड़ी में सऊदी टैंकरों पर हमलों की खबरों ने फिर से आपूर्ति की चिंता बढ़ा दीं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 83 सेंट यानी 1.04 फीसदी बढ़कर 80.28 डॉलर प्रति बैरल हो गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 61 सेंट यानी 0.81 फीसदी बढ़कर 75.83 डॉलर पर पहुंच गया।

केसीएम ट्रेड के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वॉटरर ने कहा, ट्रेडरों को जून में कुछ समय के लिए हुए उस सहमति करार के बारे में अब भी याद है। इसलिए यह चिंता स्वाभाविक है कि कोई भी नया समझोता फिर से उतना ही नाजुक साबित हो सकता है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार को कहा था कि ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले शिपिंग मार्ग के भौगोलिक सहयोग पर सहमत हो गए हैं और एक संयुक्त घोषणा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बशर्ते कि कुछ तीसरे पक्ष इसमें दखल न दें। ईरान और ओमान के बीच प्रस्तावित समझौता अमेरिका-ईरान विवाद खत्म करने में मददगार होगा। इससे खाड़ी से होर्मुज स्ट्रेट आने वाले जहाजों पर तेहरान को नियंत्रण मिल जाएगा। ईरान के एक वरिष्ठ सूत्र और दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने बुधवार को रॉयटर्स को यह जानकारी दी। यह ईरान को अब तक मिली सबसे बड़ी रियायतों में से एक है। फरवरी के आखिर में संघर्ष शुरू होने से पहले होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर में रोजाना

होने वाली तेल और एलपीजी की आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता था।

भूराजनीतिक जोखिम बरकरार

वॉटरर ने कहा, जब तक वॉल्यूम में लगातार और पुष्टि वाली बढ़ोतरी नहीं दिखती, तब तक बाजार आपूर्ति से जुड़े जोखिम को मानता रहेगा। शिपिंग आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई में खाड़ी देशों से कच्चे तेल और कंडेनसेट का निर्यात काफी हद तक स्थिर रहा और युद्ध से पहले के स्तर से करीब 40 फीसदी नीचे बना रहा।

पांच सूत्रों के अनुसार ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उसकी जमीन पर अमेरिका का कोई नया हमला होता है तो वह पूरे इलाके में अहम एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमला करेगा। तेहरान, वॉशिंगटन के सबसे करीबी क्षेत्रीय सहयोगियों को धमकाकर सैन्य कार्रवाई की लागत बढ़ाना चाहता है।

यमन के ईरान-समर्थक हूती विद्रोहियों ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के लाल सागर वाले बंदरगाह शहर यानबू के तट के पास एक सऊदी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया और पास की अदन की खाड़ी में एक और सऊदी तेल टैंकर पर भी मिसाइल से हमला दागा। सऊदी अरब की ओर से इन दोनों घटनाओं में से किसी की भी पुष्टि नहीं की गई।

अलग तरह की योजनाएं शुरू करेंगे म्युचुअल फंड

एनएफओ में तेजी के बीच पहली बार कम से कम 4 विशिष्ट योजनाएं बाजार में लाने की तैयारी

अभिषेक कुमार
मुंबई, 6 अगस्त

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को अलग दिखाने के लिए म्युचुअल फंड कंपनियां खास तरह की नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी में लगी हैं। फंड कंपनियों को हाल ही में कई ऐसे फंडों के लिए मंजूरी मिली है, जिन्हें उद्योग में पहली बार पेश किया जाएगा। इन फंड हाउस में मोतीलाल ओसवाल एमएफ का मल्टी थीमेटिक ऐक्टिव फंड ऑफ फंड्स, डीएसपी म्युचुअल फंड का फाइनैंशियल सर्विसेज सेक्टोरल डेट फंड, अल्फाग्रेप म्युचुअल फंड का लिक्विड ओमनी एफओएफ और एचडीएफसी एएएफ का एफटीएसई इंडिया ईटीएफ शामिल हैं। आने वाले हफ़्तों में आने वाली इन योजनाओं को हाल में हुए नियामकीय बदलाव के तहत मंजूरी मिली है।

मोतीलाल ओसवाल का मल्टी थीमेटिक ऐक्टिव एफओएफ कई थीमेटिक इक्विटी फंडों में निवेश करेगा, जिससे निवेशकों को एक ही योजना के जरिये अलग-अलग थीम में निवेश का मौका मिलेगा। डीएसपी का फाइनैंशियल सर्विसेज सेक्टोरल डेट फंड मुख्य रूप से बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय क्षेत्र की दूसरी कंपनियों द्वारा जारी डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। यह सेक्टर विशिष्ट डेट फंडों में से पहला होगा। अल्फाग्रेप का लिक्विड ओमनी एफओएफ लिक्विड फंड श्रेणी में पहला एफओएफ होगा और यह ऐक्टिव और पैसिव लिक्विड योजनाओं में निवेश करेगा। एचडीएफसी का एफटीएसई इंडिया ईटीएफ उन चुनिंदा योजनाओं में से एक होगा, जो किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत पर केंद्रित इंडेक्स को ट्रैक करती हैं।

हाल के हफ्तों में शेयर बाजार में स्थिरता और निवेशकों के भरोसे में सुधार को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले महीनों में फंड हाउस नए फंड लॉन्च करने की रफ्तार बढ़ाएंगे। नए फंड ऑफर (एनएफओ) के लिए साल की पहली छमाही सुस्त रही। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में ऐक्टिव इक्विटी एनएफओ संग्रह छह साल के निचले स्तर पर आ गया क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव और

अनिश्चितता का असर निवेशकों की दिलचस्पी पर पड़ा।

आने वाले समय में लॉन्च होने वाले फंडों में बैलेंस्ड हाइब्रिड फंडों की वापसी की उम्मीद है, जो लगभग एक दशक से ज्यादा समय से करीब-करीब गायब थे। सेबी की 2017 की योजना वर्गीकरण प्रक्रिया के बाद इस श्रेणी की लोकप्रियता कम हो गई थी। इस प्रक्रिया ने फंड हाउस को एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर दिया था। ज्यादातर फंडों ने एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम को चुना क्योंकि उनमें इक्विटी कराधान का लाभ मिलता था।

इस साल की शुरुआत में स्थिति तब बदली जब सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को दोनों श्रेणियों में योजना लाने की इजाजत दे दी। हाल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड ने इस श्रेणी में एक स्कीम लॉन्च की है। एसबीआई एमएफ, कोटक एमएफ और बड़ौदा बीएनपी पारिबा एमएफ को नियामकीय मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि वे जल्द ही अपनी स्कीम लॉन्च करेंगे। उद्योग के जानकारों का मानना है कि यह श्रेणी उन निवेशकों को पसंद आ सकती है, जो इक्विटी-डेट में 40-60 फीसदी का ज्यादा अनुमानित आवंटन चाहते हैं। यह बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से अलग है, जहां बाजार के बारे में फंड मैनेजर के नजरिए से इक्विटी निवेश में काफी बदलाव हो सकता है।

इंटरमीडियरीज के लिए एकल खिड़की मंजूरी की योजना : सेबी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 6 अगस्त

बाजार नियामक की सालाना रिपोर्ट में चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि सेबी 2026-27 के अपने नियामकीय एजेंडे के तहत सिक्योरिटीज लेंडिंग ऐंड बॉरोइंग (एसएलबी) ढांचे में बदलाव करने, कई मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस (एमआईआई) से जुड़े इंटरमीडियरीज के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने की योजना बना रहा है। साथ ही सेबी सेतु पोर्टल लॉन्च करने की भी योजना तैयार हो रही है।

पांडेय ने कहा, आने वाले साल में सेबी नियामक से जुड़ी गैर-जरूरी चीजों की पहचान करने और उन्हें हटाने, प्रक्रिया से जुड़ी जरूरतों को आसान बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि नियामक पूंजी सृजन को बढ़ावा देने के लिए कैश इक्विटी मार्केट को और मजबूत करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, प्राइस डिस्कवरी को बेहतर बनाने और कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट के बीच आपसी जुड़ाव को आसान बनाने के लिए सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग स्कीम में बदलाव की जरूरत है। हम भारत के कमोडिटी मार्केट (कृषि व गैर-कृषि) को मजबूत करने के अपने एजेंडे पर काम करना जारी रखेंगे।

पांडेय ने कहा कि सेबी कई एमआईआई से जुड़े इंटरमीडियरीज़ के लिए नियमों का पालन करने का बोझ कम करने के लिए एक सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएगा। नियामक सेबी सेतु पोर्टल लॉन्च करने, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करके कॉरपोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने और एमआईआई के लिए लंबे समय के तकनीकी रोडमैप के जरिये क्वांटम-युग के साइबर-सिक्योरिटी जोखिमों के लिए बाजारों को तैयार करने की भी योजना बना रहा है।

उन्होंने कहा, 2025-26 के दौरान हमने कई सुधार किए, लेकिन भविष्य के लिए हमारा विजन और भी बड़ा है। जैसे-जैसे भारतीय प्रतिभूति बाजार का दायरा और जटिलता बढ़ रही है, सेबी एक ऐसे प्रोएक्टिव, तकनीक आधारित नियामकीय माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो कारोबार करने में आसानी, बाजार को गहरा बनाने और बाजार की अखंडता बनाए रखने पर केंद्रित हो।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Central Office: "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
(IRDAI Reg. No. 512 Dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,796.14	165,360.78	119,753.87	538,378.50
2	Net Profit before tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
3	Net Profit before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
4	Net Profit after tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,584.25	23,467.18	10,957.05	57,453.15
5	Paid-up Equity Share Capital	12,650.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	178,489.50	171,230.89	132,156.14	171,230.89
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each)				
	1. Basic: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42
	2. Diluted: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42

Key number of Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are as under:

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,420.12	164,981.77	119,333.04	536,748.56
2	Profit before tax	13,583.96	23,403.28	11,006.14	57,453.78
3	Profit after tax	13,492.03	23,420.43	10,986.51	57,418.55

Notes:
1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
2. The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and the Corporation's website **(www.licindia.in)**. The same can be accessed by scanning the QR code below.
3. IRDAI has, vide IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026, mandated insurance companies to prepare financial statements in accordance with the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) w.e.f April 1, 2026. The Corporation has obtained forbearance from IRDAI to defer adoption of Ind AS by one year, and accordingly has prepared its financial results as per the accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP) and Schedule II of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations 2024.

For and on behalf of the Board of Directors

DINESH PANT
Managing Director
(DIN: 11134993)

Place:- Mumbai
Date:- 06-08-2026

Crèche @ workplace: Govt says no focused audit yet

AUHONA MUKHERJEE
New Delhi, 6 August

Crèches mandatory, but...

- Under the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, establishments employing 50 or more workers are required to provide a crèche facility
- Women employees are allowed four visits to the crèche each day, including the interval for rest
- A recent Economic Advisory Council to the Prime Minister working paper argued that expanding childcare services should form part of a strategy to develop India's care economy

MISSING IN THE workforce

The Ministry of Labour and Employment told Parliament on Thursday that the Centre has not carried out any dedicated assessment or compliance audit of the mandatory crèche provision at workplaces, nearly nine years after it was introduced under the amended Maternity Benefit Act. The provision was later subsumed under the Code on Social Security, 2020.

"No specific assessment or compliance audit has been undertaken exclusively on the implementation of the mandatory crèche provision. The government does not maintain data on the number of establishments required to provide crèche facilities or the extent of compliance with the said provision," Minister of State for Labour and Employment Shobha Karandlaje told the Upper House.

The ministry said no specific assessment or compliance audit had been undertaken solely for this requirement. Instead, compliance is monitored through routine inspections by inspector-cum-facilitators, with enforcement action taken wherever violations are detected.

Employers are sensitised on statutory requirements via the Shram Suvidha Portal 2.0 and awareness programmes.

According to the reply, inspections in establishments under the sphere of the Central government have declined over the past three years, from 402 in 2023-24 to 256 in 2024-25 and 142 in 2025-26 (up to March). The number of irregularities detected also fell to 167 in 2025-26 from 248 a year earlier and 733 in 2023-24.

However, the number of irregularities rectified rose to 111 from 77 in 2024-25.

The ministry launched 15 prosecutions in 2025-26, up from 10 in the previous year and 11 in 2023-24, while convictions stood at one, compared with none in 2024-25 and six in 2023-24. A working paper by the Economic Advisory Council to the Prime Minister argued that expanding childcare services should form part of a strategy to develop care economy, recommending coordinated action across ministries to improve access to childcare and other care services.

Google's $15 bn Andhra Pradesh data centre battles water, wildlife concerns

REUTERS
Visakhapatnam, 6 August

Work to build Google's planned data centre hub is in full swing in Andhra Pradesh's Visakhapatnam with a hillside above the site stripped to red earth and terraced into steps, but a mounting opposition from environmentalists is creating hurdles for the US tech giant's $15 billion project.

The state government, however, has denied allegations that the project was fast-tracked without weighing risks to water supplies and wildlife.

But the growing opposition could become an early test for Google's biggest-ever India investment, which is facing legal challenges over its impact on water supplies and proximity to a wildlife sanctuary, a home to leopards and pangolins.

In recent weeks, activists and children have marched in Visakhapatnam city, holding banners saying "We cannot drink Data" and painting handcuffs on the Google logo, social media posts show.

"Development should not be at the cost of livelihood of the people," Raja Rama Mohan Roy, founder of non-profit Green Visakha said at the event where he presented statistics on Visakhapatnam's stressed water supply and demand.

The government says the city receives 410 million litres of water a day from its reservoirs and rivers, against a requirement of 480 million.

Rationing of water supplies is common in the city with a population of 2.5 million people.

The Andhra Pradesh High Court has asked the government to defend against allegations levelled by activist group Jal Biradari, which says the project will strain water availability.

The state in its statement to *Reuters* called activists' concerns about the project incorrect and misleading, but added it is open to feedback.

Google in a statement to *Reuters* said its project will be developed in line with applicable laws and it will implement "advanced air cooling to protect vital local water resources".

More on business-standard.com

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Central Office: "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
(IRDAI Reg. No. 512 Dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,796.14	165,360.78	119,753.87	538,378.50
2	Net Profit before tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
3	Net Profit before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
4	Net Profit after tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,584.25	23,467.18	10,957.05	57,453.15
5	Paid-up Equity Share Capital	12,650.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	178,489.50	171,230.89	132,156.14	171,230.89
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each)				
	1. Basic: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42
	2. Diluted: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42

Key number of Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are as under:

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,420.12	164,981.77	119,333.04	536,748.56
2	Profit before tax	13,583.96	23,403.28	11,006.14	57,453.78
3	Profit after tax	13,492.03	23,420.43	10,986.51	57,418.55

Notes:
1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
2. The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and the Corporation's website **(www.licindia.in)**. The same can be accessed by scanning the QR code below.
3. IRDAI has, vide IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026, mandated insurance companies to prepare financial statements in accordance with the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) w.e.f April 1, 2026. The Corporation has obtained forbearance from IRDAI to defer adoption of Ind AS by one year, and accordingly has prepared its financial results as per the accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP) and Schedule II of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations 2024.

For and on behalf of the Board of Directors

DINESH PANT
Managing Director
(DIN: 11134993)

Place:- Mumbai
Date:- 06-08-2026

Rise above the market's ups and downs with the right insight.

In the ever-changing market landscape, a broader view helps you make smarter choices. Business Standard delivers sharp market analysis, timely intelligence, and expert Q&As—giving you the clarity to navigate the markets with confidence.

Stocks in the News
Stay ahead everyday with our special feature on key stocks—tracking sharp upward or downward trends and the reasons behind every move.

The Compass
Explore in-depth analysis of select stocks and sectors—current trends, key drivers, and potential opportunities to watch.

Q&A
Kickstart your week with interviews featuring top business leaders—sharing sharp perspectives and market outlooks, every Monday morning.

To book your copy,
SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

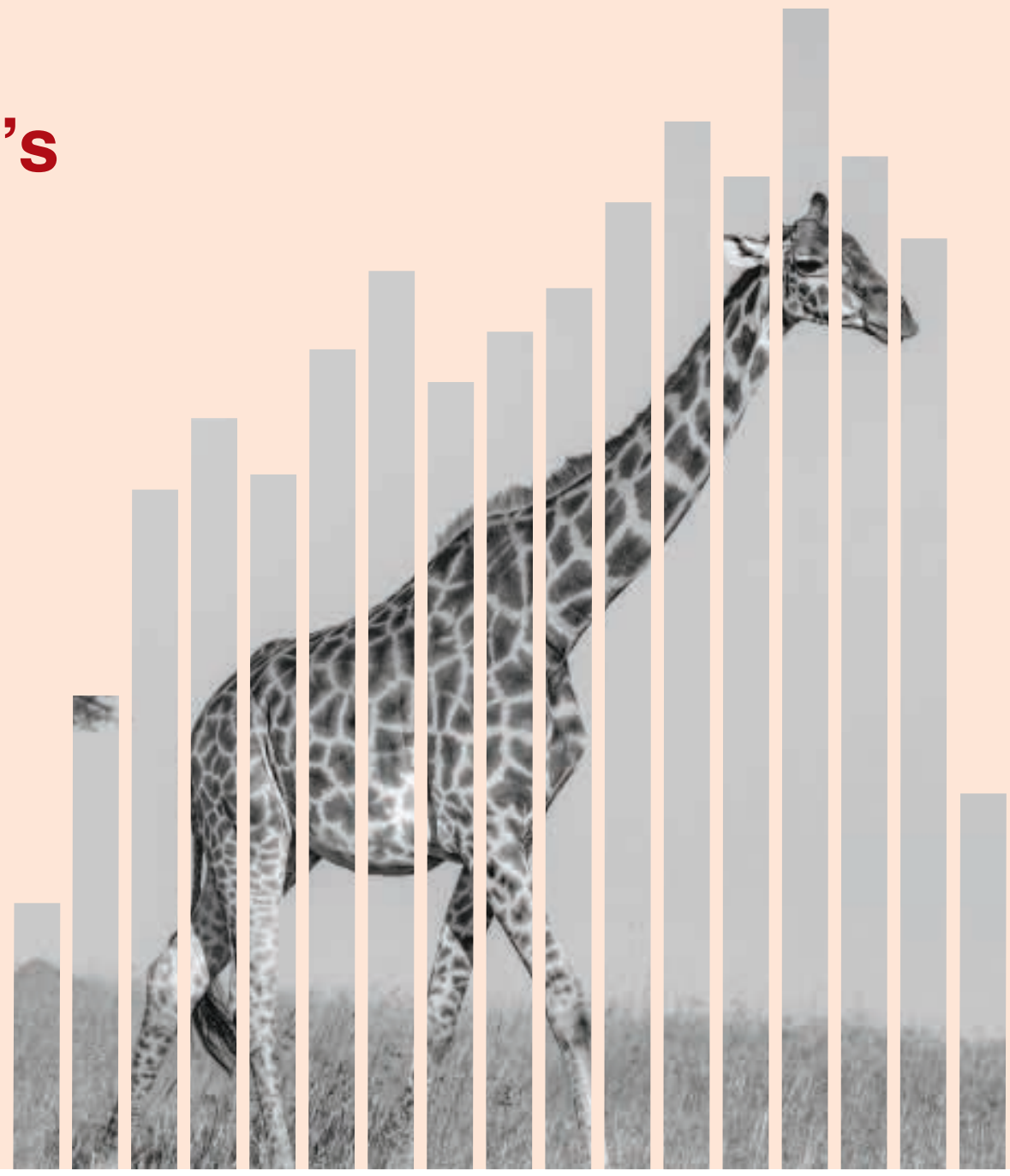

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business.standard business-standard

business-standard.com

निवडक

युवती विभागाच्या राज्य प्रमुखपदी निर्मला नवले

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या महाराष्ट्र प्रदेश युवती विभागाच्या राज्यप्रमुखपदी पुणे जिल्ह्यातील कारेगावच्या माजी सरपंच निर्मला नवले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील नियुक्तीपत्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी जारी केले. मुंबईतील 'देवगिरी' या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते निर्मला नवले यांना नियुक्तीचे अधिकृत पत्र प्रदान करण्यात आले.

अनुदानित शाळांना करातून वगळा –प्रभू

मुंबई : मुंबईतील अनुदानित व विनाअनुदानित मराठी शाळांवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करणे गरजेचे आहे. यासाठी मराठी शाळांना मालमत्ता करातून वगळण्यात यावे याकडे ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी पत्राद्वारे पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे लक्ष वेधले आहे. पालिका क्षेत्रातील अनुदानित व विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या मराठी शाळांवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि शाळा बंद पडण्यापासून वाचवण्यासाठी शैक्षणिक कामकाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्यात यावी, अशी मागणी प्रभु यांनी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

आम्ही उद्योगिनीतर्फे मंगळागौरचे आयोजन

मुंबई : आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठानतर्फे संस्कृती जपण्यासाठी गेली ४ ते ५ वर्षे महिलांसाठी मंगळागौरचे आयोजन केले जात आहे. यामध्ये मंगळागौरच्या दिवशी खेळले जाणारे विविध पारंपरिक खेळ खेळण्यात येतात. यावर्षी मंगळागौरचे आयोजन शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी साने गुरुजी विद्यालय, भिकोबा वामन पाठारे मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (प.) येथे करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाची वेळ संध्याकाळी ७ ते रात्री १० अशी आहे.

म्हाडा मुंबई मंडळाची लॉटरी नवीन वर्षात

■ अनामत रक्कम राहणार अर्जदाराच्या खात्यामध्ये ■ नवीन लॉटरीपासून निर्णय लागू

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत नवीन वर्षाच्या प्रारंभी जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात घरांची लॉटरी काढण्यात येईल, अशी घोषणा म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी गुरुवारी मुंबईत केली. या लॉटरीपासून अर्जदारांना अनामत रक्कम म्हाडाकडे न भरता स्वतःच्या बँक खात्यामध्ये जमा ठेवावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची २ हजार ६४० घरांची लॉटरी गुरुवारी वांद्रे पश्चिमेकडील रंगशारदा सभागृहात काढण्यात आली. यावेळी जयस्वाल बोलत होते. "म्हाडाच्या वतीने दरवर्षी घरांसाठी लॉटरी काढली जाते. आजचा सोडत सोहळा हा त्याच नियमित प्रक्रियेचा एक भाग आहे. या वेळच्या लॉटरीला काहीसा विलंब झाला, याबाबत मी सर्व नागरिकांची मनःपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो. गेल्या ३ वर्षांत म्हाडाने राज्यभरात २५ लॉटरी जाहीर करून नागरिकांना ५० हजार घरे दिली आहेत. यापुढे ही मालिका सुरू राहणार असून जानेवारी २०२७ मध्ये म्हाडाची पुढील लॉटरी घोषित करण्यात येईल," असे त्यांनी सांगितले.

सध्या महामुंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून साडेसात लाख घरे उभारण्यात येत आहेत. म्हाडा ९२५ एकर जागेवर क्लस्टर प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६५ हजार मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल. याशिवाय म्हाडाला ३० हजार घरे आणि खासगी क्षेत्राला १ लाख घरे उपलब्ध होणार आहेत.

म्हाडाला घरे न देणाऱ्या बिल्डरांना तुरुंगात पाठवा

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर अनेक बिल्डरांनी म्हाडाला घरे दिलेली नाहीत. या बिल्डरांवर केवळ एफआयआर दाखल करून त्यांना कारागृहात पाठवावे, अशी भूमिका कौशल्य ,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगराचे सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मांडली. लोढा म्हणाले की, नागरिकांच्या तक्रारी तातडीने सोडविण्यासाठी वॉर्ड निहाय स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वास्तुविशारद, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या सल्लागार समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. या समित्यांमुळे नागरिक आणि म्हाडा प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होऊन स्थानिक स्तरावरील समस्या तातडीने सोडविण्यास मदत होईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात हॉस्टेल - डॉ. पंकज भोयर

संपूर्ण देशातून लोक मुंबईत राहायला येत असल्यामुळे येथे घरांना प्रचंड मागणी आहे. म्हाडाच्या घरांसाठी येणाऱ्या अलोट अर्जांवरून लोकांना हक्काचे घर हवे असल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणूनच अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे घर मिळावे या ध्येयाने सरकार काम करत आहे. नागपूर हे आता एक मोठे औद्योगिक शहर म्हणून विकसित होत असल्यामुळे तिथेही मोठ्या प्रमाणावर घरे तयार केली जात आहेत. सरकार काही नवीन धोरणे आणत असून त्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष घरे बांधली जात आहेत. तसेच नोकरदार महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हॉस्टेल उभारण्यात येणार आहे.

मोपलवारांच्या कंपनीची कमी बोली

रेडिओ क्लब पॅसेंजर जेट्टीचे कंत्राट मिळण्याची शक्यता

मुंबई : मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळील रेडिओ क्लब येथे नव्या प्रवासी आणि पर्यटन जेट्टीच्या बांधकामासाठी माजी आयएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने सर्वात कमी रकमेची बोली लावल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली.

मोडर्न इंजिनिअरिंग अँड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंपनीने १४ जुलै रोजी उघडण्यात आलेल्या आर्थिक बोलीमध्ये अंदाजित खर्चापेक्षा ४.४१ टक्के कमी, म्हणजेच २०४.९९ कोटी रुपयांची बोली सादर केली आहे. हा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संचालक मंडळापुढे ठेवला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाचे आदेश जारी केले जातील. कामाचे आदेश मिळाल्यापासून कंत्राटदाराला हे काम पूर्ण करण्यासाठी २४ महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल.

या जेट्टी प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारकडून २२९.२८ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या 'सागरमाला' कार्यक्रमांतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागाने हा प्रकल्प राबवला जात आहे. गेटवे ऑफ इंडिया हे मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचे आणि व्यग्र जलवाहतूक केंद्र असून तेथील प्रवासी व पर्यटन पायाभूत सुविधा वाढवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या गेटवे ऑफ इंडिया येथील पाच जेट्टींवरून घारापुरी (एलिफंटा गुहा), मांडवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आणि हार्बर क्रूझसाठी फेरी सेवा चालवल्या जातात.

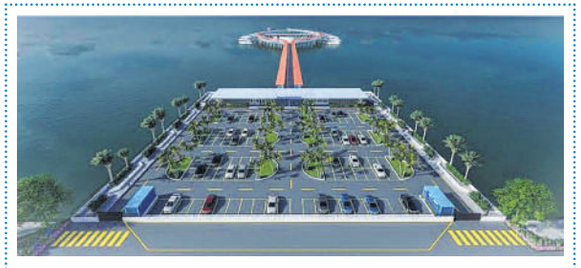

ताण कमी होणार

सध्याच्या सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याने येथे मोठी गर्दी होते. याचा नाहक त्रास प्रवासी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि दिव्यांगांना सहन करावा लागतो. नवी जेट्टी उभारल्यामुळे सध्याच्या जेट्टींवरील ताण कमी होईल, तसेच प्रवाशांना सुरक्षित व सोयीस्कर रीतीने बोटीत चढण्या-उतरण्याची सुविधा मिळेल. याशिवाय जलवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढून प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रकल्पात कोणत्या सुविधा

प्रस्तावित पायाभूत सुविधांमध्ये ८० मीटर बाय ८० मीटरचा टर्मिनल प्लॅटफॉर्म, आधुनिक टर्मिनल इमारत, २१४ मीटर लांबीचा पोहोच मार्ग, १० बोटींसाठी बर्थिंग जेट्टी, भव्य प्रतीक्षागृह, सुरक्षा तपासणी यंत्रणा, स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अग्निसुरक्षा यंत्रणा, सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स आणि लँडस्केप हरित क्षेत्र आदी सुविधा आहेत.

मुंबईकरांचा खड्डेप्रवास सुरूच

दोन महिन्यांत ३,६७२ तक्रारींचा पाऊस

मुंबई : 'खड्डेमुक्त मुंबई'चा दावा करणाऱ्या मुंबई महापालिकेसमोर खड्ड्यांचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत मुंबईकरांनी खड्ड्यांबाबत तब्बल ३,६७२ तक्रारी महापालिकेकडे नोंदवल्या असून, शहरातील रस्त्यांची दूरवस्था अद्यापही कायम असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे महापालिका, एमएमआरडीए, बीपीटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर प्राधिकरणांच्या अखत्यारितील रस्त्यांबाबतही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

१० जून २०२६ पासून आतापर्यंत महापालिकेला एकूण ५,८६९ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ३,६७२ तक्रारी खड्ड्यांबाबत, तर सुमारे २,२०० तक्रारी इतर स्वरूपाच्या होत्या. याशिवाय एमएमआरडीए, एमएमआरसीएल, बीपीटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील ४१० तक्रारींचाही यात समावेश आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, प्राप्त झालेल्या सुमारे ९० टक्के तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

दरम्यान, मुंबईतील सुमारे २,०५० किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे काम सुरू असून अनेक रस्ते पूर्ण झाले आहेत. आणखी काही रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाला ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. मात्र तोपर्यंत डांबरी रस्त्यांवरील खड्डे मुंबईकरांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

खड्ड्यांबाबत तक्रारी नोंदविण्यासाठी महापालिकेने 'पॉटहोल क्विकफिक्स ॲप' विकसित केले असून 'माय बीएमसी', व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि १९१६ हेल्पलाइनवरही तक्रारी स्वीकारल्या जात आहेत.

सर्वाधिक तक्रारी

एस वॉर्ड (भांडुप, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, नाहूर, पवई) – ३७८, एम-पूर्व (मानखुर्द, देवनार) – ३६८, एम-पश्चिम (चेंबूर, टिळक नगर, छेडा नगर) – ३१५, एल वॉर्ड (कुर्ला, साकीनाका, चांदिवली) – २८३, आर-मध्य (बोरिवली) – २२० आणि पी-दक्षिण (गोरेगाव) – २०७ अशा नोंदविण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहर विभागाच्या तुलनेत उपनगरांमध्ये खड्ड्यांची समस्या अधिक तीव्र असल्याचे चित्र आहे.

गणेशमूर्तींच्या आगमनालाही खड्ड्यांचे विघ्न

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या गणेशमूर्तींचे आगमन सुरू झाले असतानाच रस्त्यांवरील खड्डे आणि असमतल रस्त्यांमुळे मंडळांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पुढील काही दिवसांत गणेशमूर्तींच्या आगमन होणार असून रस्ते तातडीने सुरक्षित आणि समतल करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर उभे आहे.

मतदार अर्ज १७ ऑगस्टपर्यंत भरा!

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे आवाहन

मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत मतदारांनी १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मतदार अर्ज भरून संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्याकडे जमा करावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने गुरुवारी केले.

भारत निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार मतदान अर्ज भरून स्वाक्षरी केलेल्या मतदारांची नावे २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदारयादीत समाविष्ट केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोणत्याही व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदारयादीत नोंदवता येत नाही. त्यामुळे ज्या मतदारांची नावे एकाहून अधिक ठिकाणी असतील, त्यांनी सध्याच्या वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणासाठीच गणनाअर्ज भरावा. इतर ठिकाणच्या अर्जावर 'आधीच नोंदणीकृत' अशी नोंद करावी.

'जेन-झी'चे प्रश्न रास्त, आंदोलन हे संवादाचे माध्यम

सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा तरुण पिढीशी संवाद

मुंबई : लोकशाहीत आंदोलन हे संवादाचे एक वैध माध्यम असून त्याचा उद्देश मतभेद निर्माण करणे नव्हे, तर सर्वसंमती घडवून आणणे हा असावा, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

नीट पेपर फुटीप्रकरणी नुकत्याच झालेल्या तरुणाईच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले. मुंबईत 'इंडियाज इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स' (आयआयएमयूएन) च्या १५व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुमारे २,००० 'जेन झी', 'जेन अल्फा' सदस्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

भारतातील शिक्षणव्यवस्थेबाबत व्यक्त केली जाणारी चिंता रास्त असल्याचे सांगत त्यांनी या क्षेत्रावरील खर्च 'जीडीपी'च्या ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे समर्थन केले. "संवादातून समस्या सुटल्या नाहीत तर लोक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात, परंतु या सर्व प्रयत्नांचा हेतू सर्वसंमती निर्माण करणे हाच असावा," असे भागवत यांनी स्पष्ट केले.

'जेन-झी' या नव्या पिढीच्या मागण्या आणि चिंता रास्त असून त्यांच्या प्रामाणिकपणावर आपला विश्वास आहे. जुन्या पिढ्यांच्या तुलनेत आजची तरुण पिढी प्रत्येक गोष्टीला तार्किक उत्तरे, आपुलकी आणि आदर शोधते, असेही त्यांनी नमूद केले.

सोशल मीडियावर बंदी घालणे हा उपाय नाही

"सोशल मीडियावर बंदी घालणे हा त्यावरचा उपाय नाही. बंदी घातल्यास अशा गोष्टी गुप्तमार्गाने अधिक पसरतात. समाजाने स्वतःहून स्वयंशिस्त बाळगली पाहिजे आणि ऑनलाइन मिळणाऱ्या माहितीची खात्रीशीर स्रोतांकडून पडताळणी केल्याशिवाय विश्वास ठेवू नये. कृत्रिम तंत्रज्ञानाद्वारे बनावट व्हिडिओ बनवले जाऊ शकतात, त्यामुळे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच १० लाख फॉलोअर्स असलेल्या इन्फ्लुएन्सर्सने आपल्या अनुयायांची जबाबदारी भान ठेवले पाहिजे," असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

महिलेची तक्रार; अधिकारी निलंबित

मुंबई : महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या गैरवर्तनाच्या तक्रारीनंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रशासकीय अधिकारी इरफान पठाण यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महापालिका मुख्यालयात कार्यरत महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पॉश) स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत समितीच्या चौकशीत पठाण दोषी आढळल्याने त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली.

महापौर रितू तावडे यांनी ७ मे रोजी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून पठाण यांना तातडीने निलंबित करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. हा प्रकार गंभीर स्वरूपाचा असून तातडीने कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते. तक्रारीनंतर पॉश अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने चौकशी करून पठाण यांना दोषी ठरवले.

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Central Office: "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
(IRDAI Reg. No. 512 Dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,796.14	165,360.78	119,753.87	538,378.50
2	Net Profit before tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
3	Net Profit before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
4	Net Profit after tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,584.25	23,467.18	10,957.05	57,453.15
5	Paid-up Equity Share Capital	12,650.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	178,489.50	171,230.89	132,156.14	171,230.89
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each)				
	1. Basic: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42
	2. Diluted: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42

Key number of Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are as under:

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,420.12	164,981.77	119,333.04	536,748.56
2	Profit before tax	13,583.96	23,403.28	11,006.14	57,453.78
3	Profit after tax	13,492.03	23,420.43	10,986.51	57,418.55

Notes:
1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
2. The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and the Corporation's website **(www.licindia.in)**. The same can be accessed by scanning the QR code below.
3. IRDAI has, vide IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026, mandated insurance companies to prepare financial statements in accordance with the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) w.e.f April 1, 2026. The Corporation has obtained forbearance from IRDAI to defer adoption of Ind AS by one year, and accordingly has prepared its financial results as per the accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP) and Schedule II of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations 2024.

For and on behalf of the Board of Directors

DINESH PANT
Managing Director
(DIN: 11134993)

Place:- Mumbai
Date:- 06-08-2026

₹5-10L insurance for 1.6L Govindas

Kalpesh Mhamunkar
MUMBAI

Ahead of the Dahi Handi festival, the state government has expanded the insurance scheme's scope with the inclusion of 1.6 lakh Govindas, citing the "growing number of participants". The Sports Department announced the decision on Thursday, saying the enhanced ambit aims to strengthen financial security for Govindas and their families in the event of accidents.

Under the scheme, ₹10 lakh compensation will be provided in case of accidental death or permanent total disability. Those losing a hand, leg or an eye in an accident will be eligible for ₹5 lakh compensation, while hospitalisation expenses for injuries will be covered up to ₹1 lakh.

The state government has already recognised the formation of Dahi Handi human pyramids as an adventure sport, in line with directions issued by the Bombay High Court and the Supreme Court. It has also framed safety guidelines to minimise risks during the festival. In addition, Govindas injured during the celebrations are entitled to free treatment at government and semi-government hospitals.

The Sports Department said the insurance scheme will be implemented through a government insurance company selected on the basis of a premium of ₹75 or less per participant. The expenditure on the scheme will be met from the State Sports Development Fund.

Registration and verification of eligible Govindas will be carried out by the Maharashtra State Govinda Association. Only participants who meet the prescribed age criteria, undergo practice sessions and take part in the festival will be covered under the scheme.

Wholesale mkts need same accountability as eateries

Wholesale yards need modern cold storage, waste handling, and water and hygiene infrastructure as non-negotiable requirements

By invitation
Ankieta Kothari

Walk past a restaurant in New York and the letter grade is on the door. An 'A' means the most recent sanitary inspection scored 0-13 points, a 'B' or 'C' signals progressive levels of violation. The grades are public, unannounced inspections are routine and the information is available online. Singapore has refined its approach further with the SAFE framework, grading establishments on sustained track record rather than a single snapshot and linking higher ratings to proper food safety management systems. These systems do not eliminate bad operators overnight, but they shift power. The consumer is no longer dependent on the chance that a determined commissioner will arrive with a team on a particular Tuesday.

Mumbai, and India more broadly, still operates largely on a different logic. FSSAI licences must be displayed, and recent Maharashtra orders have pushed calorie and allergen information on menus of larger chains, free potable water, and stricter cold-chain and hygiene norms. Yet there is no mandatory, visible, routinely updated public hygiene score on the entrance of an ordinary restaurant or school canteen. Inspection findings remain largely internal until a high-profile suspension makes news. Compliance is often reactive.

The secondary market for expired goods and the synthetic milk networks thrived not because no one knew the law, but because the probability of consistent detection and transparent consequence was low. The same applies upstream: wholesale markets need the same visibility and continuous accountability that restaurants are only now beginning to face. What needs to change is structural. A simple, mandatory letter or numerical hygiene rating system publicly displayed, linked to recent unannounced inspections, and available online would force continuous rather than crisis-driven compliance.

Government and institutional canteens (courts, Mantralaya, municipal buildings, schools) must be inspected on the same schedule and to the same standards as private ones, with results published. Traceability requirements already being tightened for milk need to extend more rigorously across the packaged and perishable supply chain, with real penalties for the logistics and disposal failures that enable the expired-goods secondary market. Wholesale yards require modern cold storage, waste handling, water and hygiene infrastructure as non-negotiable conditions of operation, not afterthoughts of redevelopment.

Mundhe's drive has performed a public service by making the invisible visible. The cockroaches in elite kitchens, the shampoo in the milk, the quiet recirculation of expired stock, and the sudden seriousness with which school menus are being rewritten are all useful shocks. Charisma and social-media momentum can sustain pressure for a season. Durable safety, however, requires a policy architecture in which every citizen can see, at a glance, what they are walking into.

This is the last part of a two-part series

Ankieta Kothari is the founder of The Bombay Blueprint, a public platform chronicling Mumbai's architecture, heritage and evolving urban landscape

Khar tree-fall: Survivor home after 3 months

FPJ News Service
MUMBAI

Harshita Kumar, 21, who suffered severe head injuries when a tree fell on an auto-rickshaw in May, has finally returned home after spending nearly three months in hospital. Doctors described her recovery as a long and challenging journey.

The incident, which claimed the life of her teenage friend, took place on May 10 on Linking Road in Khar West. A large tree from an under-construction site fell on the auto-rickshaw in which Kumar, her friend Aarika Shrivastav, 15, and the latter's sister were travelling. Shrivastav succumbed a week later, while Manasvi escaped with minor injuries.

Harshita's father, Harish, confirmed her discharge and said that she still has a long recovery ahead. They will now begin neuro-physiotherapy sessions from next week. A case has been filed against Bluestone Construction for culpable homicide.

Dharavi redvpt plan clears rly land hurdle

Sweety Bhagwat
MUMBAI

The process to clear railway land, which is part of the Dharavi redevelopment project, is in full swing. So far, 379 structures have been demolished, while 890 tenements have been vacated. Meanwhile, construction of a 36-storey rehabilitation building is progressing simultaneously at the site.

According to sources, around 3,500 hutments are located in Sector 6 of Meghwadi-Ganesh Nagar in Dharavi, which falls on railway land. The vacated structures are awaiting electricity meter disconnection before demolition is carried out in the coming weeks.

Officials said the rehabilitation process has made significant progress, with most of the remaining residents either signing rehabilitation agreements or undergoing document verification before shifting to alternate accommodation. The project had witnessed protests from a section of residents of the Ganesh Nagar-Meghwadi area. However, sources said many of them have since participated in the grievance redressal process.

Of the nearly 125 residents who had opposed the eviction, around 80 have appeared before the Dharavi Redevelopment Project (DRP) to present their claims. Eviction notices have now been issued to the remaining around 40 residents who did not appear before the DRP despite being given multiple opportunities for a hearing, sources said.

According to sources, the first allotments in the rehab building will be made to railway employees, in accordance with the agreement between the project implementing agency and the railways. Officials said the redevelopment is being executed in phases, with demolition and rehabilitation proceeding simultaneously to ensure the land is cleared while eligible occupants are rehabilitated. Once the railway staff are accommodated, the rehab of other eligible beneficiaries under the project will continue.

FDA inspects 2 food outlets on IIT-B campus

Shreya Jachak
MUMBAI

The Food and Drug Administration (FDA) recently inspected two food outlets operating on the IIT Bombay campus, following which the institute said it is awaiting the detailed inspection report and will implement all recommendations made by the food regulator.

The institute's spokesperson said, "Few of our eateries were reviewed and suggestions and recommendations were provided by the FDA. We are awaiting the detailed report. We are keen on making all improvements and ensuring compliance." The inspections were conducted as part of the FDA's routine monitoring of food establishments to assess hygiene, food handling practices and compliance with food safety regulations.

The inspection comes amid increased scrutiny of food safety standards at educational institutions and public establishments across Maharashtra, with the FDA undertaking regular inspections to improve hygiene.

Is your paneer real? FPJ conducts LIVE test at Mumbai restaurant
Scan QR code to watch video

320km of footpaths to be obstacle-free

Shefali Parab-Pandit
MUMBAI

As part of the 'Pedestrian First' campaign, the BMC's K-West ward will cover around 320 km of footpaths in the first phase. Of the 355 roads identified for action, 27 will be targeted initially, with 37.7 km of footpaths to be cleared of encroachments. K-West includes Andheri West, Vile Parle West and some parts of Santacruz. The civic body said it will also upgrade footpaths to create safer, obstruction-free pedestrian corridors.

Focusing on Vile Parle and Goregaon, the civic body is prioritising unobstructed movement for ambulances, patients, students and commuters. During Thursday's inspections of K-West and P-South (Goregaon) wards, civic chief Ashwini Bhide found illegal vehicle ramps, stalls and commercial structures occupying pedestrian spaces. She directed housing societies and shop owners to remove unauthorised ramps within a month, warning that violators will face strict action under BMC rules.

"Blocked footpaths force senior citizens, women, children and persons with disabilities to step onto busy roads, putting pedestrian safety at risk," said Bhide. Officials have been directed to remove illegal hawkers, shop extensions and other obstructions along Ram Ganesh Gadkari Marg and S V Road in Vile Parle.

At Goregaon West railway station's Bandu Gore Marg, Bhide ordered the relocation of commercial structures obstructing pedestrian movement.

Birth & death cert services go digital

FPJ News Service
MUMBAI

Amid complaints of delays in birth and death certificate registrations, the BMC's public health department has started digital services at the Civic Facility Centre (CFC) in all ward offices. A separate window has also been made available for applicants travelling abroad for education and jobs. The move follows a large number of applications for corrections in birth certificates for educational travel, foreign trips and other purposes.

Now, citizens will be able to avail themselves of online services at the CFC for child name insertion, birth/death certificate correction (for entries registered on the new CRS portal), conversion of old birth/death certificates into new QR-coded ones and marriage certificate correction.

The option to check the application status has also been made available at the CFC. Thus, citizens will no longer need to approach the medical officer to follow up on their applications.

Municipal Commissioner Ashwini Bhide has also directed that an SMS option be made available to inform citizens about the status of their applications. The BMC has also clarified that citizens will be able to apply for a new-format birth/death certificate through the Centre's Civil Registration System (CRS) portal for records registered before 2016. "Such old records may require additional verification, which may take more time. Efforts are underway to reduce the processing time," the BMC said.

Oppn clamour grows to save Neville D'Souza football ground; demand to junk proposal

Shefali Parab-Pandit
MUMBAI

A Congress delegation met BMC Commissioner Ashwini Bhide on Thursday, demanding the withdrawal of the controversial proposal to convert the Neville D'Souza football ground at Bandra Reclamation into a convention and exhibition centre. The plan is set to be placed before the civic house for approval next week. Shiv Sena (UBT) has also been protesting the move to change the football ground's reservation in the development plan (DP) 2034.

Congress group leader Ashraf Azmi said the ground is not merely a piece of land but a cornerstone of Mumbai's football ecosystem. He claimed that around 400 youth clubs and 300 senior clubs use the ground every year, providing training opportunities to nearly 8,000 to 10,000 young footballers. Raising a point of order before the standing committee on Thursday, Azmi urged Chairman Prabhakar Shinde to junk the proposal. "At a time when the youth are already facing issues like paper leaks and limited opportunities, taking away a crucial sports ground will further hurt their prospects. If playgrounds are also taken away, how will young athletes find space to train and progress?" asked Azmi.

Shiv Sena (UBT) corporator Yashodhar Phanse opposed the proposal, stating that party MLA Aaditya Thackeray has already raised objections against "handing over valuable open spaces for commercial use". The Bandra-Kurla Complex already has a convention centre, so there is no need to change the reservation of this playground, Phanse asserted. He warned that the party would strongly oppose any move to alter the reservation.

According to the BMC, the proposed reservation change is based on a request from the Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA), which owns the 8,450 sq m ground. The Authority has claimed that the plot was originally earmarked for a convention complex under the Bandra Reclamation layout approved by the state government in 1983.

However, during the preparation of DP 2034, the land was marked as a playground as it was being used for football activities. Civic officials argued that since there is no convention or exhibition facility in the vicinity, converting the reservation to an Exhibition Centre would address an existing infrastructure gap.

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Central Office: "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
(IRDAI Reg. No. 512 Dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,796.14	165,360.78	119,753.87	538,378.50
2	Net Profit before tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
3	Net Profit before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items	13,686.39	23,456.69	10,985.77	57,523.88
4	Net Profit after tax, Exceptional and / or Extraordinary items	13,584.25	23,467.18	10,957.05	57,453.15
5	Paid-up Equity Share Capital	12,650.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	178,489.50	171,230.89	132,156.14	171,230.89
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each)				
	1. Basic: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42
	2. Diluted: (in ₹) (not annualised for three / six months)	10.74	18.55	8.66	45.42

Key number of Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are as under:

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-26	31-Mar-26	30-Jun-25	31-Mar-26
		REVIEWED	AUDITED	REVIEWED	AUDITED
1	Premium Income (Gross)[1]	127,420.12	164,981.77	119,333.04	536,748.56
2	Profit before tax	13,583.96	23,403.28	11,006.14	57,453.78
3	Profit after tax	13,492.03	23,420.43	10,986.51	57,418.55

Notes:
1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
2. The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and the Corporation's website **(www.licindia.in)**. The same can be accessed by scanning the QR code below.
3. IRDAI has, vide IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026, mandated insurance companies to prepare financial statements in accordance with the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) w.e.f April 1, 2026. The Corporation has obtained forbearance from IRDAI to defer adoption of Ind AS by one year, and accordingly has prepared its financial results as per the accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP) and Schedule II of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations 2024.

For and on behalf of the Board of Directors

DINESH PANT
Managing Director
(DIN: 11134993)

Place:- Mumbai
Date:- 06-08-2026